

मेहबूब अली और अन्य

बनाम

राजस्थान राज्य

(आपराधिक अपील संख्या. 808/2010)

27 अक्टूबर, 2015

[एच. एल. दत्त, सीजेआई और अरुण मिश्रा, जे.]

साक्ष्य अधिनियम, 1872:धारा 27-आरोपी का कथन जिससे अन्य आरोपी व्यक्तियों की पहचान और गिरफ्तारी होती है और नकली मुद्रा नोटों की बरामदगी होती है जो जानकारी पुलिस को ज्ञात नहीं होती है-उसके कथन की स्वीकार्यता-आयोजित:आरोपी के कथन से अन्य आरोपी व्यक्तियों की संलिप्तता साबित करने वाले तथ्य का पता चला और परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला से स्पष्ट रूप से पता चला कि सह-आरोपी ने साजिश में काम किया-ये तथ्य पुलिस की जानकारी में नहीं थे इसलिए आरोपी का कथन जिसमें तथ्य का पता चलता है, धाराओं में निहित प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट रूप से स्वीकार्य था।27 अधिनियम जो एस. एस. में निहित पुलिस अभिरक्षा के तहत किए गए स्वीकारोक्ति की अस्वीकृति के बारे में सामान्य प्रावधानों के लिए एक अपवाद बनाता है।25 और अधिनियम की धारा 26-दंड संहिता, 1860-एस. एस.4898, 489 सी.

न्यायालय द्वारा अपीलों को खारिज करते हुए, अभिनिर्धारित किया गया :-

1. साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 में प्रावधान है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस अधिकारी के सामने किया गया कोई भी इकबालिया स्वीकारोक्ति साबित नहीं किया जाएगा।धारा 26 में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति

द्वारा पुलिस अधिकारी की हिरासत में रहते हुए की गई कोई भी स्वीकारोक्ति, जब तक कि यह जी. एम. मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में नहीं की जाती है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं होगी। धारा 27 एक परंतुक के रूप में है, यह बताती है कि आरोपी से प्राप्त जानकारी को कितना साबित किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को लागू करने के लिए, इकबालिया कथन के स्वीकार्य हिस्से को एक ऐसे तथ्य के रूप में मिला जाना चाहिए जो खोज का तत्काल कारण था, केवल वही कानूनी साक्ष्य का हिस्सा होगा और बाकी नहीं। एक कथन में यदि आरोपी से कुछ नया पाया जाता है या बरामद किया जाता है जो आरोपी का खुलासा कथन दर्ज होने से पहले पुलिस की जानकारी में नहीं था, तो साक्ष्य में स्वीकार्य है। [पारस 12 और 13] [561-सी-एफ]

2. यह स्पष्ट है कि आरोपी 'एम' और 'एफ' द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, अन्य आरोपी 'ए' को गिरफ्तार किया गया था। यह तथ्य कि 'ए' जाली नोटों के साथ काम कर रहा था, पुलिस की जानकारी में नहीं था। अभियुक्त 'एम' और 'एफ' ने 'ए' की पहचान की और अंततः बयानों से नकली मुद्रा नोटों के उपयोग के गिरोह का पता चला। इस प्रकार, आरोपी 'एम' और 'एफ' द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट रूप से स्वीकार्य थी जिसके कारण आरोपी 'ए' की पहचान और गिरफ्तारी हुई और 'ए' नकली मुद्रा नोटों के कब्जे से बरामद किया गया। पी41 और पी42 ज्ञापनों के माध्यम से आरोपी 'एम' और 'एफ' द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पुलिस द्वारा आरोपी 'ए' की संलिप्तता के बारे में तथ्य का पता चला है जो पुलिस की जानकारी में नहीं था। इस प्रकार आरोपी 'एम' और 'एफ' का कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 द्वारा स्पष्ट रूप से सहेजा गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को स्पष्ट रूप से हटा दिया गया था। तत्काल मामला। आरोपी व्यक्तियों के कथन से अन्य आरोपी व्यक्तियों की संलिप्तता साबित करने वाले तथ्य का पता चला है और

परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आरोपी ने साजिश में काम किया जैसा कि निचली निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी मिला है। यह स्पष्ट है कि 'एम' और 'एफ' के कथन के अनुसार एक तथ्य की खोज हुई थी। सह-अभियुक्त को उनके द्वारा की गई पहचान के आधार पर पकड़ा गया था। वह नकली नोटों का कारोबार कर रहा था, जिसके माध्यम द्वारा पुलिस को इसकी जानकारी मिली। जाली नोटों की बरामदगी भी 'ए' से की गई। इस प्रकार उक्त आरोपी को सह-आरोपी 'ए' के बारे में जानकारी थी जिसे उनके कहने पर और उनकी पहचान के आधार पर पकड़ा गया था। ये तथ्य पुलिस की जानकारी में नहीं थे, इसलिए तथ्य की खोज करने वाले आरोपी व्यक्तियों के बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में निहित प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट रूप से स्वीकार्य हैं, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 में निहित पुलिस हिरासत के तहत किए गए स्वीकारोक्ति की अस्वीकृति के बारे में सामान्य प्रावधानों के लिए एक अपवाद बनाता है। [पैरा 15,20] [562-ई-एच; 563-ए-सी; 567-जी-एच; 568-ए-सी]

राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) बनाम नवजोत संधू उपनाम
अफसान गुरु (2005)11 एस.सी.सी.600:2005(2) पूरक।-एससीआर 79;
पुलुकुरी कोट्टाया और ओआरएस अन्यसम्राट ए. आई. आर. 1947
पी. सी. 67; महाराष्ट्र राज्य अन्य दामु गोपीनाथ शिंदे और अन्य।
एआईआर 2000 एससी 1691:2000 (3) एससीआर 880; इस्माइल
अन्य सम्राट एआईआर 1946 सिंध 43; सूबेदार और अन्य। वी.राजा-
सम्राट AIR 1924 सभी। 207-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

2005(2) पूरक एस. सी. आर.79

पर निर्भर

पैरा 16

ए.आई.आर.1947 पी. सी. 67	पर निर्भर	पैरा 16
2000(3)एस. सी. आर. 880	पर निर्भर	पैरा 17
ए.ए.आई.आर.1946 सिंध 43	पर निर्भर	पैरा 18
ए.आई.आर.1924 सभी 207	पर निर्भर	पैरा 19

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय : 2010 दाण्डिक अपीलीय संख्या 808।

राजस्थान के उच्च न्यायालय, जयपुर की एस.बी.सी.आर.एल. की अपील क्रमांक 39/2006 में पारित न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 28.05.2009 से।

के साथ

आपराधिक अपील क्रमांक 1088 /2010

शेखर नाफडे, संजय आर. हेगड़े, अरुणाभ चौधरी, गैनिलुंग पनमेई, अनुपम लाल दास, आर. के. कपूर, रेखा गिरि (अनीस अहमद खान के लिए) अपीलार्थियों के लिए।

जयंत भट्ट, पी. एल., बी. श्रवण शंकर, अजय चौधरी, पुनीत परिहार, (रुचि कोहली के लिए), मिलिंद कुमार प्रत्यर्थागण के लिए।

न्यायालय का निर्णय, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, द्वारा पारित किया गया :

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा दाण्डिक अपीलीय और अन्य संबंधित मामलों में सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक आई. डी. 2 के खिलाफ अपीलों को प्राथमिकता दी गई है, जिससे अपीलकर्ताओं की धारा 489 सी के तहत अपराध करने के लिए दोषसिद्धि और सजा को 3 साल के आर. आई. के लिए बरकरार रखा गया है, भा.दं.सं. सी. की धारा 120 बी. भा.दं.सं. सी. के साथ पठित धारा 489 बी के लिए पांच साल का आर. आई. और प्रत्येक पर आई. डी. 3 का जुर्माना; चूक में एक महीने के साधारण कारावास से गुजरना पड़ता है। अपीलार्थी महबूब अली और फिरोज को

दोषी ठहराया गया और भा.दं.सं. सी. की धारा 120 बी के साथ पठित धारा 489 बी के तहत 5 साल के आर. आई. और 1,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। अन्य आरोपी व्यक्तियों लियाकत अली और पूरन मल को भी दोषी ठहराया गया था।

2. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 2003 की 6.1.2004 प्राथमिकी आर. No. 459 पर राजस्थान राज्य के जयपुर के पुलिस स्टेशन रामगंज में पंजीकृत किया गया था। आरोपी पूरन मल के कब्जे से Rs.100 मूल्य के 5 नोट मिलातीन करेंसी नोट एक ही नंबर के थे। शेष दो करेंसी नोटों पर भी एक ही नंबर था जो स्पष्ट रूप से जाली थे। उन्हें मेमो-पी 6 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया और रिकवरी मेमो पी-7 तैयार किया गया। भा.दं.सं. की धारा 1208 के साथ पठित धारा 489 सी के तहत मामला पंजीकृत किया गया था। पूछताछ करने पर पूरन मल ने बताया कि उसे महबूब, फिरोज और राम गोपाल से नोट मिले थे। महबूब और फिरोज को आरोपी पूरन मल द्वारा दी गई जानकारी पर गिरफ्तार किया गया था। पूरन मल के कब्जे से राम गोपाल के घर के 900/- के नोट बरामद किए गए। महबूब और फिरोज ने पुलिस को सूचित किया कि उन्होंने एक जू अली से मुद्रा नोट प्राप्त कर लिए हैं, और वे पहचान करेंगे कि अंजू अली को दिल्ली ले जाया गया था। उनके द्वारा की गई पहचान पर अंजू अली को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके कब्जे से रुपये के नकली नोट बरामद किए गए। अंजू अली ने बदले में बताया कि वह आरोपी माझर से मुद्रा नोट प्राप्त करता था। अंजू अली की सूचना और पहचान पर, माझर को गिरफ्तार किया गया और उसकी तलाशी लेने पर, Rs.48,220/- के मूल्य के नकली नोट बरामद किए गए। माझर ने बदले में बताया कि वह लियाकत अली से नकली नोट प्राप्त करता था। लियाकत अली को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके कब्जे से रुपये के नोट बरामद किए गए। उसके पास से आईडी 1 मूल्य के कुछ अर्ध-निर्मित मुद्रा नोट और जाली नोट बनाने के

उपकरण भी बरामद किए गए और उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उसकी कार से 2 लाख रुपये के अतिरिक्त जाली नोट बरामद किए गए।

3. नकली नोट पुरन मल, अंजू अली, मझहर और लियाकत अली के कब्जे से बरामद किए गए हैं। बरामद नोटों को भारतीय सुरक्षा प्रेस, नासिक को भेजा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबंधक, पीडब्लू-16, श्याम सिंह ने कहा कि जब्त किए गए नोट नकली थे। रिपोर्ट पी-34 निवेदन की गई थी। स्टोर हाउस में सामग्री कैसे जमा की गई, इसके संबंध में साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। सुरक्षा प्रेस द्वारा भेजी गई रिपोर्टों में पी-46, पी-47, पी-48 और पी-51 शामिल हैं। एस. एच. ओ. रघुवीर सिंह ने पुरन मल, अंजू अली, मझहर आदि से बरामद वस्तुओं की पहचान की।

4. आरोपी महबूब को मेमो पी4 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने मेमो एक्स पी41 के माध्यम से जानकारी निवेदन की। आरोपी फिरोज ने मेमो एक्स पी42 के माध्यम से जानकारी निवेदन की। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत। उन दोनों ने बताया कि दिल्ली के उस्मान भाई और अंजू अली रेसिडेंट्स ने उन्हें जाली नोटों की आपूर्ति की थी और वे उनकी पहचान करेंगे। जानकारी रघुवीर सिंह द्वारा दर्ज की गई थी, 10. वह आरोपी महबूब और फिरोज को दिल्ली ले गया था। वहाँ उन दोनों ने सीलमपुर, दिल्ली के स्ट्रीट No.13 में एक मारुति कार DL-3C-V-2927 की पहचान की। उन्होंने कार में बैठे व्यक्ति की पहचान अंजू अली के रूप में भी की, जिसके लिए जापन Ex.P16 तैयार किया गया था और दो गवाहों मुकेश यादव-पीडब्लू13 और विनोद शर्मा-पीडब्लू11 के हस्ताक्षर भी प्राप्त किए गए थे। महावीर पीडब्लू24 आई. ओ. रघुवीर सिंह के साथ थे। विनोद शर्मा, पीडब्लू 11 हालांकि शत्रुतापूर्ण हो गए, उन्होंने मेमो एक्स पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए। पी16 ने पुलिस के साथ दिल्ली जाने के तथ्य का भी समर्थन किया। उन्होंने वाहन नं. आर. जे.-14 7सी 4668 और पुलिसकर्मियों को जयपुर से दिल्ली ले गया। मुकेश यादव पीडब्लू13 ने भी इस बात का

समर्थन किया कि वह अपने क्वालीस No. RJ14T-5649 से पुलिस को दिल्ली ले गया था। महबूब अली और फिरोज द्वारा अंजुअली की पहचान का भी समर्थन किया गया। मेमो पी13 के माध्यम से अंजू अली की गिरफ्तारी में और पंत की दाहिनी ओर की जेब से तलाशी लेने में, कुल रुपये के 350 जाली नोट बरामद किए गए, जो जाली भी मिला

5. अभियुक्त एक जू अली ने 7.1.2004 दिनांकित सूचना ज्ञापन पी43 प्रस्तुत किया था कि उसने माझाड़ में Rs.500 के मूल्यवर्ग के मुद्रा नोट प्राप्त किए थे और वह माझाड़ की पहचान करेगा। अंजू अली द्वारा पहचाने जाने की जानकारी के आधार पर, माझर को रात 8.15 बजे गिरफ्तार किया गया, जब वह आई. एस. बी. टी. के पास खड़ा था, जहाँ मेट्रो रेलवे निर्माणाधीन था। पीडब्लू11 और पीडब्लू13 दोनों ने ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है। मेमो पी-31 के माध्यम से माझर को गिरफ्तार किया गया। माझर मुद्रा की तलाशी लेने पर उसके बाएं पैर के मोजे में रखे छोटे थैले से पी19 ज्ञापन के माध्यम से Rs.500, Rs.100 और Rs.20 के नोट बरामद किए गए। इसके अलावा, विनोद शर्मा पीडब्लू11, मुकेश यादव पीडब्लू13 और महावीर सिंह पीडब्लू24 ने भी जानकारी की वसूली और प्रस्तुत करने के तथ्य का समर्थन किया है। माझर से 220 के नोट बरामद किए गए।

6. अभियोजन पक्ष ने सभी 28 गवाहों में पूछताछ की और 53 दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया। बचाव में 3 गवाहों से पूछताछ की गई। निचली निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को उपरोक्त रूप में दोषी ठहराया है और सजा सुनाई है, इसलिए अपील की गई है।

7. यह अपीलार्थी महबूब अली और मोहम्मद की ओर से निवेदन गया था। फिरोज ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज आरोपी व्यक्तियों का इकबालिया कथन स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरोपी व्यक्ति पुलिस की हिरासत में थे। आरोपी महबूब अली और मोहम्मद फिरोज से कोई बरामदगी नहीं हुई है। इस प्रकार उनकी सजा अवैध है और इसे दरकिनार किया जा सकता है। आरोपी अंजू अली और माझर की ओर में यह निवेदन गया है कि उनमें वसूली साबित नहीं हुई है और उनकी दोषसिद्धि कानूनन गलत है।

8. अंजू अली और मझहर की अपील के संबंध में यह स्पष्ट है कि अंजू अली को महबूब और फिरोज द्वारा मेमो एक्स के माध्यम से दी गई जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। पी41 और पी42 और उसकी पहचान उपरोक्त आरोपी व्यक्तियों द्वारा की गई थी जब वह स्ट्रीट No.13, सीलमपुर, दिल्ली में मारुति कार में था। विनोद पीडब्लू-11 और मुकेश यादव पीडब्लू 13 ने जापन पी16 पर हस्ताक्षर किए हैं। इस तथ्य का समर्थन महावीर सिंह पीडब्लू24 ने भी किया है। हालांकि विनोद शत्रुतापूर्ण हो गया लेकिन उसने जापन पी 16 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए हैं और पुलिस के साथ दिल्ली जाने के तथ्य का समर्थन किया है। मुकेश यादव, पीडब्लू-13, ने भी समर्थन किया है कि वह पुलिस को दिल्ली ले गया था और महबूब और फिरोज ने बताया है कि अंजू अली कार में थी जिसके आधार पर उसे मेमो पी3क्यू के माध्यम से गिरफ्तार किया गया था। अंजू अली की तलाशी लेने पर, वसूली जापन पी-26 के माध्यम से रुपये मूल्य के 350 जाली नोट जब्त किए गए।

9. आरोपी माझर के संबंध में जानकारी पी43 आरोपी अंजू अली द्वारा दी गई थी। अंजू अली ने माझर की पहचान तब की जब वह आईएसबीटी के पास खड़ा था। मुकेश पीडब्लू-13 ने मेमो पी43 साबित किया है। विनोद पीडब्लू11 ने भी पी-31 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। रिकवरी मेमो पी19 के माध्यम में, माझाड़ में Rs.500,

Rs.100 और Rs.20 के मूल्यवर्ग के नोट बरामद किए गए, जो कुल मिलाकर Rs.48,220/- थे। भारतीय सुरक्षा प्रेस, नासिक रोड द्वारा निवेदन उपरोक्त रिपोर्टों के आधार पर वे नकली साबित हुए हैं। सभी नोट जाली मिलापी. डब्ल्यू. 16 के प्रबंधक श्याम सिंह ने भारतीय सुरक्षा प्रेस को मुद्रा नोट भेजने को साबित किया है। मुद्रा नोट जाली साबित हुए हैं और अपीलों में इस संबंध में रिपोर्ट की शुद्धता पर सवाल नहीं उठाया गया है।

10. महबूब अली और फिरोज द्वारा दायर अपील में, उनकी ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील द्वारा निवेदन गया था कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज आरोपी का इकबालिया कथन स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उनके कब्जे से मुद्रा नोटों की कोई बरामदगी नहीं हुई है। पुलिस हिरासत में किया गया इकबालिया स्वीकारोक्ति अस्वीकार्य था, इसलिए अपीलकर्ता महबूब और मोहम्मद को दोषी ठहराने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था। फिरोज।

11. मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि शुरू में आरोपी पूरन मल को गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे से जाली नोट बरामद किए गए थे। उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कि आरोपी महबूब और फिरोज द्वारा उसे करेंसी नोट सौंपे गए थे, उन्होंने बदले में आरोपी अंजू अली की गिरफ्तारी के लिए पूरे क्रम का खुलासा किया है। अंजू अली को महबूब अली और फिरोज द्वारा पहचाने जाने पर गिरफ्तार किया गया था जब उन्हें जयपुर से दिल्ली ले जाया गया था और अंजू अली से जाली नोट बरामद किए गए थे। अंजू अली ने एक अन्य सह-आरोपी माझर की पहचान की, जिसके कब्जे से नकली मुद्रा नोट भी बरामद किए गए और माझर द्वारा प्रदान की गई जानकारी अंततः लियाकत अली की गिरफ्तारी का कारण बनी, जिसके कब्जे से जाली मुद्रा नोट भी बरामद किए गए और नकली मुद्रा नोट छापने के उपकरण के साथ अर्ध-मुद्रित मुद्रा नोट भी बरामद किए गए।

12. साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 में प्रावधान है कि किसी पुलिस अधिकारी के सामने किया गया कोई भी इकबालिया स्वीकारोक्ति किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं होगा। धारा 26 में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी की हिरासत में रहते हुए किया गया कोई भी इकबालिया स्वीकारोक्ति, जब तक कि यह मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में नहीं किया जाता है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं होगा। धारा 27 एक परंतुक के रूप में है, यह बताती है कि आरोपी से प्राप्त जानकारी को कितना साबित किया जा सकता है।

13. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को लागू करने के लिए, इकबालिया कथन के स्वीकार्य हिस्से को एक ऐसे तथ्य के रूप में मिला जाना चाहिए जो खोज का तत्काल कारण था, केवल वही कानूनी साक्ष्य का हिस्सा होगा और बाकी नहीं। कथन में यदि आरोपी से कुछ नया पाया जाता है या बरामद किया जाता है जो आरोपी का खुलासा कथन दर्ज होने से पहले पुलिस की जानकारी में नहीं था, तो साक्ष्य में स्वीकार किया जाता है।

14. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का उल्लेख तब होता है जब कोई "तथ्य" सामने आ जाता है। अधिनियम की धारा 3 में तथ्य को परिभाषित किया गया है। वही नीचे उद्धृत किया गया है:

"तथ्य का अर्थ है और इसमें शामिल हैं -

(1) कोई भी चीज, चीजों की स्थिति, या चीजों का संबंध, जो इंद्रियों द्वारा होने में सक्षम है;

(2) कोई भी मानसिक स्थिति जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति सचेत है।

दृष्टांतः

(क) यह एक तथ्य है कि कुछ वस्तुएँ एक निश्चित स्थान में एक निश्चित आदेश में व्यवस्थित हैं।

(ख) यह एक तथ्य है कि एक व्यक्ति ने कुछ सुना या देखा है।

(ग) कि एक आदमी ने कुछ शब्द कहे, यह एक तथ्य है।

(घ) कि एक व्यक्ति एक निश्चित राय रखता है, एक निश्चित इरादा रखता है, सद्भावना से कार्य करता है, या धोखाधड़ी से कार्य करता है, या एक विशेष अर्थ में एक विशेष शब्द का उपयोग करता है, या एक निर्दिष्ट समय पर किसी विशेष संवेदना के प्रति सचेत है या था, यह एक तथ्य है।

(ई) यह एक तथ्य है कि एक व्यक्ति की एक निश्चित प्रतिष्ठा होती है।"प्रासंगिक "।-एक तथ्य को दूसरे के लिए प्रासंगिक कहा जाता है जब एक प्रासंगिकता अपराधों से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधानों में निर्दिष्ट किसी भी तरीके से दूसरे के साथ जुड़ा होता है।"

15. यह स्पष्ट है कि आरोपी महबूब अली और फिरोज द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अन्य आरोपी अंजू अली को गिरफ्तार किया गया था। तथ्य यह है कि अंजू अली जाली नोटों के साथ काम कर रही थी। पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी। दोनों आरोपीों के कथन से तथ्य का पता चला है और सह-आरोपी की गिरफ्तारी हुई है जिसकी पुलिस को जानकारी नहीं है। उन्होंने उसकी पहचान की और अंततः बयानों से नकली नोटों के उपयोग के रैकेट का पता चला है। इस प्रकार उपरोक्त आरोपी व्यक्तियों द्वारा सूचना जापनों के माध्यम से दी गई जानकारी स्पष्ट रूप से स्वीकार्य है जिसके कारण आरोपी एन जू अली की पहचान और गिरफ्तारी हुई है और जैसा कि पहले ही

कहा जा चुका है कि अंजू अली के पास से नकली मुद्रा नोट बरामद किए गए हैं। पी41 और पी42 जापनों के माध्यम से आरोपी महबूब और फिरोज द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पुलिस को आरोपी अंजू अली की संलिप्तता के बारे में तथ्य का पता चला है जो पुलिस की जानकारी में नहीं था। पुलिस को आरोपी अंजू अली के साथ-साथ इस तथ्य की भी जानकारी नहीं थी कि वह उसके पास से बरामद किए गए नकली नोटों का कारोबार कर रहा था। इस प्रकार उपरोक्त आरोपी महबूब और फिरोज का कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 द्वारा स्पष्ट रूप से सहेजा गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल मामले में स्पष्ट रूप से हटा दिया गया था। आरोपी व्यक्तियों के कथन से अन्य आरोपी व्यक्तियों की संलिप्तता साबित करने वाले तथ्य का पता चला है और परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आरोपी ने साजिश में काम किया जैसा कि निचली निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी मिला है।

16. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम नवजोत संधू उपनाम अफसान गुरु [(2005) 11 एस. सी. सी. 600] के इस अदालत ने धारा 27 में निर्दिष्ट तथ्य की खोज के प्रश्न पर विचार किया है। इस अदालत ने बहुतायत पर विचार किया है। निर्णयों की और पुलुकुरी कोर्टा अन्य और सम्राट [ए. आई. आर. 1947 डी. पी. सी. 67] में निर्णय की व्याख्या की। और इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :

"125. हमारा विचार है कि कोर्टाया मामला [ए. आई. आर. 1947 पी. सी. 67] इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि "तथ्य की खोज" को उत्पन्न या मिला वस्तु के बराबर नहीं माना जा सकता है। तथ्य की खोज इस तथ्य के कारण होती है कि आरोपी द्वारा दी गई जानकारी किसी विशेष स्थान पर सूचना देने वाले के अस्तित्व के बारे में ज्ञान या मानसिक जागरूकता का प्रदर्शन करती है।

126. अब हम इस अदालत के उदाहरणों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जो कोट्टाया पूर्व निर्णय के मार्ग का अनुसरण करते थे। कोट्टाया मामले में निर्णय के अनुपात को इस अदालत के कई फैसलों में रेखांकित किए गए उद्धरण में दर्शाया गया है।

127. कोट्टाया मामले में अनुपात का सार इस अदालत द्वारा महाराष्ट्र राज्य बनाम दामू मामले में समझाया गया था। थॉमस न्यायमूर्ति ने देखा कि: (एस. सी. सी. पी. 283, पैरा 35)

"पुलुकुरी कोट्टाया बनाम सम्राट (सुप्रा) में प्रिवी काउंसिल का निर्णय इस व्याख्या का समर्थन करने के लिए सबसे अधिक उद्धृत प्राधिकरण है कि धारा में परिकल्पित 'तथ्य की खोज' उस स्थान को शामिल करती है जहां से वस्तु उत्पन्न की गई थी, आरोपी का ज्ञान इसके बारे में लेकिन दी गई जानकारी उस प्रभाव से स्पष्ट रूप से संबंधित होनी चाहिए।"

मोहम्मद इनायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य [1976 1 एस. सी. सी. 828], सरकारिया, न्यायमूर्ति ने यह स्पष्ट करते हुए कि धारा 27 में "तथ्य की खोज" अभिव्यक्ति किसी भौतिक या भौतिक तथ्य तक ही सीमित नहीं है जिसे इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, और इसमें एक मानसिक तथ्य शामिल है, पुलुकुरी कोट्टाया मामले (उपरोक्त) में जो निर्धारित किया गया था, उसका सार देते हुए अर्थ समझाया। पीठ की ओर से बोलते हुए विद्वान न्यायाधीश ने इस प्रकार टिप्पणी की: (एस. सी. सी. पी. 832, पैरा 13)

"अब यह उचित रूप से तय हो गया है कि 'तथ्य की खोज' अभिव्यक्ति में न केवल उत्पन्न भौतिक वस्तु शामिल है, बल्कि वह स्थान भी है जहाँ से इसे उत्पन्न किया जाता है और इसके बारे में आरोपी का ज्ञान भी शामिल है (पुलुकुरी कोट्टाया बनाम सम्राट (सुप्रा) देखें; उदय भान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1962 पूरक (2) एस. सी. आर. 830)"

17. महाराष्ट्र राज्य अन्य दामू गोपीनाथ शिंदे और अन्य। [ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 1691] आरोपी द्वारा दिया गया कथन कि बच्चे के शव को एक विशेष स्थान पर ले जाया गया था और घटनास्थल से बरामद एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा सह-आरोपी की मोटरसाइकिल के टेल लैंप का हिस्सा मिला गया था। इस तथ्य का पता लगाने वाला कथन कि आरोपी एक विशेष मोटरसाइकिल द्वारा मृत शरीर को उक्त स्थान तक ले गया था, साक्ष्य में स्वीकार्य होगा। इस अदालत ने इस प्रकार निर्धारित किया है:

"36. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में अंतर्निहित मूल विचार बाद की घटनाओं द्वारा पुष्टि का सिद्धांत है। यह सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि किसी कैदी से प्राप्त किसी भी जानकारी के आधार पर की गई खोज में कोई तथ्य पाया जाता है, तो ऐसी खोज इस बात की गारंटी है कि कैदी द्वारा प्रदान की गई जानकारी सच है। जानकारी प्रकृति में इकबालिया या गैर-उत्तेजक हो सकती है, लेकिन अगर इसके परिणामस्वरूप किसी तथ्य की खोज होती है तो यह एक विश्वसनीय जानकारी बन जाती है। इसलिए विधायिका ने इस तरह की जानकारी को स्वीकार्य हिस्से को न्यूनतम तक सीमित करके साक्ष्य के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी। अब यह अच्छी तरह से तय

हो गया है कि किसी वस्तु की पुनर्प्राप्ति किसी तथ्य की खोज नहीं है जैसा कि धारा में परिकल्पित है।पुलुकुरी कोट्टाया बनाम सम्राट ए. आई. आर. 1947 पी. सी. 67 में प्रिवी काउंसिल का निर्णय इस व्याख्या का समर्थन करने के लिए सबसे अधिक उद्धृत प्राधिकरण है कि धारा में परिकल्पित "तथ्य की खोज" उस स्थान को शामिल करता है जहां से वस्तु का उत्पादन किया गया था, आरोपी का ज्ञान इसके बारे में लेकिन दी गई जानकारी का उस प्रभाव से स्पष्ट रूप से संबंध होना चाहिए।

37. इसमें कोई संदेह नहीं है कि साक्ष्य में स्वीकार की जाने वाली जानकारी जानकारी के उस हिस्से तक ही सीमित है जो "स्पष्ट रूप से इस तरह से खोजे गए तथ्य से संबंधित है"।लेकिन स्वीकार्यता प्राप्त करने के लिए जानकारी को इतना छोटा करने की आवश्यकता नहीं है कि यह असंवेदनशील या समझ से बाहर हो जाए।स्वीकार की गई जानकारी की सीमा समझ के अनुरूप होनी चाहिए।इस मामले है पीडब्लू 44 द्वारा पता चला कि ए-3 मुकुंद थोराट दीपक के शव को मोटरसाइकिल पर मौके पर ले गया था।

38. विशेष जानकारी से तथ्य की खोज कैसे हुई?इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसी नहर से दीपक का शव बरामद होना पीडब्लू 44 द्वारा प्राप्त जानकारी से पूर्व था।यदि आरोपी से जानकारी प्राप्त करने के बाद और उसके बाद कुछ भी बरामद नहीं किया गया होता, तो किसी भी तथ्य की कोई खोज नहीं होती।लेकिन जब उस स्थान से टूटे हुए कांच का टुकड़ा बरामद किया गया और वह टुकड़ा ए-2 गुरुजी की मोटरसाइकिल के टेल लैंप का हिस्सा मिला गया, तो यह सुरक्षित रूप

से माना जा सकता है कि जांच अधिकारी को इस तथ्य का पता चला कि ए-2 गुरुजी ने शव को उस विशेष मोटरसाइकिल पर मौके पर ले जाया था।

39. तथ्य की उक्त खोज को ध्यान में रखते हुए, हम यह मानने के लिए इच्छुक हैं कि ए-2 गुरुजी द्वारा प्रदान की गई जानकारी कि दीपक के शव को मोटरसाइकिल पर विशेष स्थान तक ले जाया गया था, साक्ष्य में स्वीकार्य है। इसलिए वह जानकारी अभियोजन पक्ष के मामले को उपरोक्त सीमा तक साबित करती है।"

18. इस्माइल बनाम सम्राट [ए. आई. आर. 1946 सिंध 43] मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप पुलिस द्वारा एक अन्य सह-आरोपी मिला गया था, वहां सह-आरोपी के ठिकाने के बारे में आरोपी द्वारा पुलिस को दिए गए कथन को आरोपी के खिलाफ साक्ष्य के रूप में धारा 27 के तहत स्वीकार्य माना गया था।

19. सूबेदार और अन्य बनाम राजा-सम्राट [ए. आई. आर. 1924 ऑल. 207] यह अभिनिर्धारित किया गया कि आरोपी द्वारा खुद को और दूसरों को फंसाने वाले कथन को 'प्रथम सूचना रिपोर्ट' नहीं कहा जा सकता है। हालांकि यह माना गया कि हालांकि इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में नहीं माना जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दी गई जानकारी के रूप में किया जा सकता है। यह इस प्रकार आयोजित किया गया था:

"सरकारी गवाह और एक अपीलार्थी को व्यावहारिक रूप से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने उस अधिकारी को बयान दिए जिसने उन्हें अपराध स्वीकार करते हुए गिरफ्तार किया था। वे आगे बढ़े और

गिराह के अन्य सदस्यों की सूची दी। इसके बाद अधिकारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को लिखित में एक रिपोर्ट दी, जिसमें उन्हें मिली जानकारी थी, जिसमें गिरफ्तार किए गए दो लोगों से प्राप्त उन अन्य व्यक्तियों के नाम भी शामिल थे। किसी न किसी तरह, विद्वान न्यायाधीश ने इस पुलिस रिपोर्ट को, जो एक केवल एक स्वीकारोक्ति की रिपोर्ट है, "प्रथम सूचना रिपोर्ट" के रूप में वर्णित किया है। अब प्रथम सूचना रिपोर्ट दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत एक रिपोर्ट का एक सर्वविदित तकनीकी विवरण है, जो एक संज्ञेय अपराध की पहली जानकारी देता है। यह आमतौर पर फरियादी या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। यह भाषा आरोपी द्वारा दिए गए कथन पर लागू नहीं होती है। एक आरोपी व्यक्ति द्वारा दिए गए कथन को प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाना मेरे लिए इतना अजीब था कि जब अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने न्यायाधीश द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के उपयोग पर हमला करने वाले तर्क को संबोधित किया, तो मैंने तर्क पर कोई ध्यान नहीं दिया। विद्वान न्यायाधीश ने महसूस किया कि वह एक स्वीकारोक्ति के साथ काम कर रहा था, लेकिन वह क्षणिक रूप से यह समझने में विफल रहा कि दस्तावेज़ स्वयं अस्वीकार्य था, और जिस एकमात्र तरीके से जानकारी पर भरोसा किया जा सकता था वह धारा 27 द्वारा था। अर्थात्, अन्य आरोपी के संबंध में, साक्ष्य देने वाला अधिकारी कह सकता है: "नारायण और ठाकुर से मिली जानकारी के परिणामस्वरूप मैंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब मैंने उन्हें गिरफ्तार किया तो उन्होंने मुझे एक कथन दिया जिसके कारण मुझे इन लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। ऐसी जानकारी

का वैध रूप से जो उपयोग किया जा सकता है वह केवल यह है कि जब मुकदमे में आरोपी के खिलाफ प्रत्यक्ष साक्ष्य दिया जाता है और आरोपी के खिलाफ साक्ष्य होता है, तो बचाव पक्ष के लिए यह पूछने के लिए खुला है कि क्या उस समय किसी विशेष आरोपी के नाम का उल्लेख किया गया था या नहीं।"

20. उपरोक्त कथनों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि महमूद अली और मोहम्मद के कथन के अनुसार एक तथ्य का पता चला था।फिरोज।सह-आरोपी को आरोपी महबूब और फिरोज द्वारा की गई पहचान के आधार पर पकड़ा गया था।वह नकली नोटों का कारोबार कर रहा था, जिसके माध्यम द्वारा पुलिस को पता चला।अंजू अली के पास से जाली नोटों की बरामदगी भी की गई। इस प्रकार उपरोक्त आरोपी को सह-आरोपी अंजू अली के बारे में जानकारी थी जिसे उनके उदाहरण और उनकी पहचान के आधार पर पकड़ा गया था।ये तथ्य पुलिस की जानकारी में नहीं थे, इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में निहित प्रावधानों के अनुसार आरोपी व्यक्तियों के बयान स्पष्ट रूप से स्वीकार्य हैं, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 में निहित पुलिस हिरासत के तहत किए गए स्वीकारोक्ति की अस्वीकृति के बारे में सामान्य प्रावधानों के लिए एक अपवाद बनाते हैं।

21. नतीजतन, हम अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।निचली निचली अदालत द्वारा और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए निर्णय और सजा का आदेश उचित मिला गया है।इस प्रकार योग्यता से रहित होने के कारण अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

अपील खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही पामाणिक माना होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।